उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड,

सिविल रिविजन नं. 39/2016

(सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत)

अर्श बरी

......संशोधनवादी बनाम

द हिमालय ड्रग कंपनी एंड अन्य

............प्रतिवादी

संशोधनवादी के अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष सिन्हा के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री विवेक पाठक।

संदर्भित मामलों की सूची:

1. (2011) 8 एससीसी 670; उत्तरांचल राज्य एवं अन्य बनाम सुनील कुमार वैश
2. 2000 (1) एससीसी 711; बी.के. नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई एवं अन्य
3. 1991............ (1) एससीसी 414; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अतुल कृष्ण शॉ एवं अन्य

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

वर्तमान सिविल पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध निर्देशित है दिनांक 19.02.2016 को 7वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा ओ.एस. 374/2009, हिमालयन ड्रग कंपनी बनाम अजहर मोहम्मद और अन्य, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, सीपीसी) के आदेश 9 नियम 7 के तहत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र संख्या 244 सी को खारिज कर दिया गया है।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि प्रतिवादी नं. 1 कंपनी ने संशोधनवादी के पूर्ववर्ती अजहर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दायर किया, और अनिवार्य निषेधाज्ञा, निषेधात्मक निषेधाज्ञा और मुकदमे में संपत्ति के संबंध में नुकसान की वसूली के लिए

प्रोफार्मा प्रतिवादियों ने वाद दायर किया। उपरोक्त वाद ओ एस नं. 374/2009 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. प्रतिवादी नं. 1 विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और उसने अपना लिखित बयान दर्ज किया।अन्य प्रतिवादियों अर्थात प्रतिवादी नं. 2 से 7 को भी समन जारी किया गया था, लेकिन उसे तामील नहीं किया गया। प्रतिवादियों को पंजीकृत डाक से सेवा देने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश नहीं दिया गया।प्रत्यर्थी नं. 1 ने प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा के लिए अनुमति मांगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया,जिसे अदालत ने अनुमति दी थी और सीधे तौर पर वादी/प्रत्यर्थी नं. 1 को दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी नं. 2 से 7 पर प्रभावी सेवा के लिए कदम उठाने की अनुमति दी गई थी। प्रकाशन के माध्यम से सेवा के बावजूद, प्रतिवादी नं. 2 से 7 विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और इस प्रकार उनके विरुद्ध दिनांक 04.08.2011 के आदेश के तहत एकपक्षीय मुकदमा चलाया गया।

4. 02.04.2012 को प्रतिवादी नं. 1 अजहर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिस्थापन के लिए मुकदमे में संशोधनवादी, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 सहित उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे।14.05.2013 को सूचना की तामील पर संशोधनवादी निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हुए, इस तथ्य से बेखबर थे कि दिनांक 04.08.2011 के आदेश के अनुसार, मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 7 होने के कारण मामले को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, प्रतिवादी नं. 1 और 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए वादी/प्रत्यर्थी नं. 1 द्वारा दो संशोधन आवेदन दायर किए गए थे, क्योंकि यह भी रिकॉर्ड पर लाया गया था कि प्रतिवादी नं. 2 की मौत मुकदमे दर्ज करने से पहले हो गई

थी।

उक्त संशोधन को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2014 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

5. तत्पश्चात, अभिलेख के निरीक्षण पर, संशोधनवादी /प्रतिवादी नं. 7 को पता चला कि दिनांक 04.08.2011 के आदेश द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

दिनांक 04.08.2011 के आदेश द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

04.08.2011.इसलिए, 26.11.2015 को संशोधनवादी ने आदेश 9 नियम 7 सी पी सी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद, वादी द्वारा दायर संशोधन आवेदन पर, उसे नोटिस दिया गया था।इसके बाद, वह विचारण न्यायालय के सामने पेश हुए लेकिन उन्हें 4.8.2011 के आदेश की जानकारी नहीं थी।यह भी कहा गया कि उन्हें प्रकाशन के माध्यम से की गई सेवा का ज्ञान नहीं हो सका।विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.02.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा आदेश 9 नियम 7 सी पी सी के तहत संशोधनवादी /प्रतिवादी नं. 7 द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ने न तो देर से आवेदन करने का कोई संतोषजनक कारण दिखाया है और न ही निर्धारित तिथि पर उनके उपस्थित न होने का उचित कारण दर्शाया है।अपने आवेदन के समर्थन में संशोधनवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया: लाल बहादुर बनाम द्वितीय अपर मुंसिफ फतेहपुर एवं अन्य (ए आई आर 2002 ऑल 360), दिल्ली डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाम शांति देवी एवं अन्य (ए आई आर 1982 एस सी 159) और रघुवर वर्स रेवेन्यू काउंसिल (1998), लेकिन विचारण न्यायालय ने यह माना कि उपरोक्त निर्णय संशोधनवादी /वादी के मामले में लागू नहीं होते हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

7. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी नं. 1/वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें संशोधनवादी को प्रतिवादी नं 7 के रूप में आरोपित किया जिसमें संशोधनवादी को प्रतिवादी नं 7 के रूप में आरोपित किया गया था।प्रतिवादियों के लिए नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी नं. 1 विचारण न्यायालय के सामने पेश हुआ और मुकदमा लड़ा।प्रतिवादी नं. 1 को छोड़कर, न तो किसी अन्य प्रतिवादी को सेवा दी गई और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 04.08.2011 के आदेश के अनुसार, विचारण न्यायालय ने माना कि प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी नं. 2 से 7 पर सेवा पर्याप्त है, लेकिन ऐसा करते समय प्रतिवादी नं. 1 को प्रतिस्थापित सेवा के लिए अनुमति देने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।लेकिन ऐसा करते समय प्रतिवादी नं. 1 को प्रतिस्थापित सेवा के लिए अनुमति देने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।हालाँकि, प्रकाशन के माध्यम से संशोधनवादी /प्रतिवादी नं. 1 पर सेवा प्रभावित हुई थी।आदेश नियम 20 सी पी सी, इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होगा, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:

20. "प्रतिस्थापित सेवाएं"

(1) जहां न्यायालय संतुष्ट है कि यह विश्वास करने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, या कि किसी अन्य कारण से सम्मन की तामील सामान्य तरीके से नहीं की जा सकती है, न्यायालय सम्मन की तामील करने के लिए

न्यायालय-भवन में किसी विशिष्ट स्थान पर उसकी एक प्रति चिपका कर आदेश देगा, न्यायालय सम्मन की तामील करने के लिए न्यायालय-भवन में किसी विशिष्ट स्थान पर और घर के कुछ विशिष्ट भाग (यदि कोई हो) पर भी उसकी एक प्रति चिपका कर आदेश देगा। जिसमें प्रतिवादी के बारे में ज्ञात हो कि वह अंतिम बार निवास करता था या व्यापार करता था या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता था, या ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि न्यायालय उचित समझता है।

(1 क) जहां उप-नियम (1) के तहत कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील करने का आदेश देता है, समाचार पत्र इलाके में परिचालित दैनिक समाचार पत्र होगा, जिसमें प्रतिवादी को वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करने, व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है।

(2) प्रतिस्थापित सेवा का प्रभाव - न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित सेवा उतनी ही प्रभावी होगी मानो वह प्रतिवादी पर व्यक्तिगत रूप से किया गया था।

(3) जहां सेवा प्रतिस्थापित की जाती है, उपस्थिति के लिए समय निर्धारित किया जाता है - जहां सेवा न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, न्यायालय प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए

ऐसा समय नियत करेगा जैसा कि मामले के लिए आवश्यकता हो सकती है।

8. सी पी सी के नियम 20 के आदेश वी केके प्रावधानों की एक सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि प्रतिस्थापित सेवा के लिए किसी भी आदेश को पारित करने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह विश्वास करने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर हो रहा है या किसी अन्य कारण से समन की तामील सामान्य तरीके से नहीं की जा सकती है।प्रतिस्थापित सेवा, सेवा के सामान्य तरीके का अपवाद है।न्यायालय को आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और इसके आदेश में निहित प्रावधानों पर उचित विचार होना चाहिए। स्पष्ट रूप से, विचारण न्यायालय नियम 20 आदेश V की आवश्यकताओं के लिए अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहा है और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है।

न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए कि प्रतिस्थापित सेवा का प्रबंधन वादी द्वारा किया जा सकता है जो प्रतिवादी को उचित अवसर से वंचित कर सकता है।

9. मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पता चलता है कि न्यायालय ने प्रतिस्थापित सेवा के आदेश को पारित करने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की है।वह भाग, दिनांक 04.08.2011 का आदेश यह नहीं दर्शाता है कि किस समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था।विचारण न्यायालय केआदेशों में कोई फुसफुसाहट नहीं है, जो यह सुझाव दे सकता है कि कभी भी विचारण न्यायालय ने अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि प्रतिवादी नं. 2 से 7, उन पर समन की तामील से बच रहे हैं या उन पर सामान्य तरीके से सम्मन तामील करना संभव नहीं है। केवल ऐसी आकस्मिकता में, अदालत समन को प्रकाशन के माध्यम से या विशिष्ट स्थान / कोर्ट हाउस और उस घर पर नोटिस

चिपकाकर तामील करने का आदेश दे सकती है, जहां प्रतिवादी अंतिम रूप से रहता है या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होता है, जो इलाके में प्रसारित होता है। जिसके बारे में अंतिम बार प्रतिवादी के निजी लाभ के लिए निवास करने या काम करने के बारे में ज्ञात है और किसी अन्य तरीके से नहीं।वर्तमान मामले में, सी पी सी के नियम 20 आदेश V का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी नं 7 को पर्याप्त रूप से तामील किया गया था।यह स्थिति होने के कारण, विचारण न्यायालय के लिए यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि प्रतिवादी नं 7 पर्याप्त तामील के बावजूद पेश नहीं हुआ, लेकिन विचारण न्यायालय ने मामले के इस कानूनी पहलू पर विचार नहीं किया और प्रतिवादी नं 7 के खिलाफ मुकदमे को एकतरफा आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

10. आक्षेपित आदेश दिनांक 19.02.2016 का अवलोकन इससे पता चलेगा कि विचारण न्यायालय ने किसी भी पक्ष द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय पर चर्चा नहीं की है और बहुत ही गुप्त तरीके से देखा है कि निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

विचारण न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि जहां तक प्रह्लाद सिंह के मामले का संबंध है, उस फैसले में निर्धारित कानून के अनुपात के अनुसार, आवेदन खारिज करने योग्य है।विचारण न्यायाधीश को अपने सामने उद्धृत मुकदमा कानूनों पर कुछ हद तक तथ्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानूनों के अनुपात पर चर्चा करनी चाहिए थी लेकिन तथ्य या कानून के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।आक्षेपित आदेश में विचारण न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया है कि आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।कानून में यह स्थापित स्थिति है कि कारणों की रिकॉर्डिंग न्याय प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है।अधिकार कारण, ध्वनि न्यायिक

प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है और अदालत के दिमाग के आवेदन को दर्शाता है। किसी निर्णय में तर्क का उद्देश्य न केवल वादी को यह दिखाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है कि उसे न्याय मिल रहा है, बल्कि अदालत के लिए एक वैध अनुशासन भी है।कारणों का बयान न्याय के अनिवार्य तत्वों में से एक है। दूसरे शब्दों में, एक प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरण के निर्णय का तर्क आवश्यक और कानून में जीवन है ।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुनील कुमार वैश्य 1** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"19. न्यायिक निर्णय सैद्धांतिक रूप से तर्कसंगत होने चाहिए और न्यायिक निर्णय की गुणवत्ता मुख्य रूप से इसके तर्क की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।उचित तर्क एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे कार्यसाधकता के लिए बलिदान नहीं किया जाना चाहिए।कारणों का कथन न केवल पक्षों के लिए निर्णय को समझना आसान बनाता है और कई बार ऐसे निर्णय सम्मान के साथ स्वीकार किए जाते हैं। न्यायाधीश को पक्षों की दलीलों का जवाब देने और उन बिंदुओं को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य करती है जो निर्णय को न्यायोचित ठहराते हैं और इसे वैध बनाते हैं और यह समाज को न्यायिक प्रणाली के कामकाज को समझने में सक्षम बनाता है और यह न्यायिक प्रणाली में लोगों के निष्ठा और विश्वास को भी बढ़ाता है।"*

12. अतुल कृष्णा शॉ 3 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है**:--**

"11. श्री चटर्जी का तर्क है कि यह अपीलकर्ता का कर्तव्य है कि वह अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को अस्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड पेश करे, जो बिना किसी आधार के है। एक अर्ध-न्यायिक जांच उन पक्षों के लिए होती है, जो अपने पक्ष में तथ्यों की कुछ स्थिति पर भरोसा करते हैं, उन्हें इसके साक्ष्य में सबूत पेश करना होता है। अधिनियम के तहत कार्यवाही एक सिविल कोर्ट में मुकदमे की तरह नहीं है और भार प्रमाण का सवाल ही नहीं उठता है। उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की मौजूदगी के अभाव में सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाला गया कि किया गया ऋण आवेदन भूखंड संख्या 2201 और 2235 से संबंधित हो सकता है, यह उचित है। अपीलीय प्राधिकारी कानून में उस खोज को खारिज करने के लिए न्यायोचित नहीं है। अन्य निष्कर्ष कि प्रत्यार्थीयो की ओर से जिन गवाहों की जांच की गई है, वे भी सबूतों पर चर्चा किए बिना और उस संबंध में कारण बताए बिना काफी लंबे समय से मत्स्य पालन के अस्तित्व का समर्थन करते हैं सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने व्यापक रूप से साक्ष्य पर विचार किया गया और ठोस कारण बताए गए , जिस पर न तो चर्चा की गई और न ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इसे अमान्य पाया गया। इस प्रकार, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड में मौजूद भौतिक साक्ष्यों की अवहेलना की, इसे अलग रखा, मछली पकड़ने के अभियान में लिप्त रहा और संदेह और अनुमानों के भार के नीचे दब हो गया। अपीलीय आदेश इसलिए

रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट कानून की प्रकट और स्पष्ट त्रुटि से दूषित है।जब इतना कुछ कहा जाना है और न्यायिक समीक्षा की जानी है, तो उच्च न्यायालय ने हमारे विचार से, रिट याचिका 8 को समय सीमा में खारिज करके कानून की त्रुटि की। सीमा में रिट याचिका।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से, जब मुकदमेबाजी को अब तक 28 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, हम इसे नए विचार के लिए उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण को भेजने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं।"

13. जहां तक एकपक्षीय आदेश का संबंध है, यह नैसर्गिक न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए। विचारण न्यायालय को एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन की अनुमति देने में उदार होना चाहिए और तकनीकी आधार पर इसे खारिज करने के बजाय योग्यता के आधार पर मामले को तय करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संहिता के प्रावधान न्याय के दास हैं और तकनीकीताओं को न्याय के प्रशासन में अदालत को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे तकनीकीताओं को अपनाने के बजाय योग्यता के आधार पर निर्णय लें। बी. के. नारायण पिल्लई 2 का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि कानून की तकनीकीताओं को पक्षों के बीच न्याय प्रशासन में अदालतों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

14. रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुकदमा प्रारंभिक स्तर पर है और मुद्दों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, परिक्षण न्यायालय को प्रतिवादी के विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के आवेदन की अनुमति देने में अधिक उदार

होना चाहिए था।ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि परिक्षण न्यायालय ने संशोधनवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करके अवैधता की है। विवादित आदेश कानून की नजर में अस्थिर है और खारिज किए जाने योग्य है।

15. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, तत्काल सिविल संशोधन की अनुमति है। विवादित आदेश दिनांक 19.02.2016 एतदद्वारा अपास्त किया जाता है। आवेदन पत्र संख्या 244C की अनुमति है।चूंकि मुकदमा काफी पुराना है, परिक्षण न्यायलय को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाए और सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद कानून के अनुसार जल्द से जल्द इस पर फैसला करे।यह स्पष्ट किया जाता है कि अनावश्यक स्थगन से बचा जाएगा और पक्षकार वाद के शीघ्र निपटान के लिए सहयोग करेंगे।

(लोक पाल सिंह, जे.)
02.07.2020

रजनी